

संक्षिप्त सार

उपराष्ट्रपति धनखड़ से मिले राजस्थान के राज्यपाल, विकास योजनाओं पर चर्चा

नई दिल्ली (एजेंसी)। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने रविवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से यहां उनके आवास पर मुलाकात की और राज्य के विकास तथा जनहित के विभिन्न मुद्दों पर बात की। राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति को शॉल ओढ़ाई और पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया। उन्होंने प्रदेश के विकास और जनता के हित से जुड़े मुद्दों के बारे में उपराष्ट्रपति को जानकारी दी। राज्यपाल बागड़े उन्हें राजस्थान में चल रही विकास परियोजनाओं और राज्य सरकार की उपलब्धियों के अलावा जनता की जरूरतों और चुनौतियों से भी अवगत कराया। इस चर्चा से राज्य की जनता को लाभ होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार राजस्थान के विकास और जनता के कल्याण के लिए हरसंभव सहायता प्रदान करेगी। उपराष्ट्रपति आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस मुलाकात की तस्वीर शेयर की गई है। इससे पहले राज्यपाल बागड़े ने शुक्रवार और शनिवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में आयोजित राज्यपालों के सम्मेलन में भाग लिया था।

वेंडरों ने अर्जित की अकूत संपत्ति, पुलिस कराएगी जब्त :

गोरखपुर (संवाददाता)। एसआईटी की जांच में सामने आया है कि मोहम्मद कमरुद्दीन उसके बेटे नवाब आरजू उर्फ लालू व नाती साहेबजादे कम मुनाफे में ही वेंडरों को स्टांप बेचते थे। 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 और 25000 का एक स्टांप बनाने में 50 रुपये का खर्च होता था। वेंडरों को यह स्टांप 150 से 300 रुपये में ही मिल जाता था। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि जेल भेजे गए वेंडरों की संपत्ति की जांच कराई जा रही है। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई होने के बाद अपराध से अर्जित संपत्ति जब्त कराई जाएगी।

अमित शाह ने चंडीगढ़ के लिए चौबीसों घंटे जलापूर्ति योजना का किया उद्घाटन



चंडीगढ़ (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को यहां मनीमाजरा में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चंडीगढ़ के लिए चौबीसों घंटे जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। इससे एक लाख से ज्यादा निवासियों को फायदा होगा। परियोजना का उद्घाटन करने के बाद अमित शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, पानी बहुत महत्वपूर्ण है, हम इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। जब यह साफ नहीं होता है तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। इस पूरे क्षेत्र के लोगों को इसके माध्यम से फिल्टर-क्लीन पानी की चौबीसों घंटे सातों दिन आपूर्ति की जाएगी। यह

समय की कसौटी पर खरा उतरेगा। अमित शाह शाम पांच बजे शहर से रवाना होने से पहले सचिवालय में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की

समीक्षा भी करेंगे। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने उनका स्वागत किया। गृह मंत्री सीधे मनीमाजरा पहुंचे और 75 करोड़ रुपये की लागत से बनी इस परियोजना का उद्घाटन किया। इससे मनीमाजरा के 1 लाख से अधिक निवासियों को लाभ मिलेगा, जिनमें मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, शिवालिक एन्क्लेव, इंदिरा कॉलोनी और शास्त्री नगर में रहने वाले लोग शामिल हैं। इस परियोजना का उद्देश्य 24 घंटे सातों दिन उच्च दबाव आपूर्ति कर जनता द्वारा पानी के स्टोरेज को न्यूनतम करके पानी की बर्बादी को रोकना है। परियोजना की अन्य विशेषताओं में रिसाव में कमी के माध्यम से जल संसाधन में

वृद्धि, स्मार्ट मीटरिंग, अंडरग्राउंड वाटर पर सीमित निर्भरता और ऊर्जा खपत की निगरानी शामिल हैं। इस परियोजना के लिए कुल 22 किलोमीटर लंबी जलापूर्ति पाइपलाइन बिछाई गई है। दो भूमिगत (अंडरग्राउंड) जलाशय स्थापित किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 20 लाख गैलन प्रतिदिन है। सिटी ब्यूटीफुल का लगभग 270 किलोमीटर लंबा जल आपूर्ति नेटवर्क, जो उच्च दबाव वाले पानी की आपूर्ति के लिए अनुकूल नहीं है, उसे भी बाद में बदल दिया जाएगा। इस परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिसके लिए शहर को 55 जिला मीटरिंग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उम्मीद है कि 2028 तक पूरे शहर को कवर कर लिया जाएगा।

पूजा खेडकर की मां मनोरमा जेल से रिहा, किसान को धमकाने के मामले में किया था गिरफ्तार

पुणे (एजेंसी)। पूर्व ट्रेनी आईएसएस पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। उन्हें एडिशनल सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें जमानत दे दी थी। मनोरमा को पिछले

सीएम मोहन यादव के काफिले से टकराया ऑटो, 13 वर्षीय बच्चे

समेत 3 लोग घायल, शाजापुर जा रहे थे मुख्यमंत्री

राजगढ़ (एजेंसी)। मध्यप्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है। यहां सीएम मोहन यादव के काफिले से एक ऑटो टकरा गया। इस हादसे में 13 साल के बच्चे समेत 3 लोग घायल हुए हैं। घटना उस सीएम मोहन शाजापुर जा मोहन यादव भोपाल से रहा था। इसी के पास हाईवे और एक ऑटो काफिले से टकरा गया। इस घटना में एक 13 साल के बच्चे समेत 3 लोग घायल हुए हैं। कलेक्टर भी हॉस्पिटल पहुंचे हैं। घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक, ऑटो में कुल चार लोग सवार थे। आरिफ ऑटो चला रहा था और साथ में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। जिस 13 साल के बच्चे को चोटें आई हैं, उसकी पहचान आमिन के रूप में हुई है। आमिन के कमर और पेट में चोट लगी है। काफिले की गाड़ी और ऑटो के बीच टक्कर इतनी जोरदार थी कि काफिले की गाड़ी असंतुलित होकर सड़क से नीचे खेत में उतर गई। सीएम के काफिले के साथ डीएम और एसपी भी चल रहे थे। वह फौरन घायलों को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। हालांकि गनीमत ये रही कि सीएम मोहन यादव को किसी तरह की चोट नहीं आई है और वह इस हादसे में बाल-बाल बचे हैं। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि सीएम के काफिले की किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है और गलती किसकी थी। घायलों का इलाज चल रहा है और किसी बड़े नुकसान की जानकारी नहीं मिली है।



महीने पुणे ग्रामीण पुलिस ने एक स्थानीय किसान को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इस मामले में पौड पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। मनोरमा खेडकर को जमीन विवाद में धमकाने के आरोप में 18 जुलाई को रायगढ़ जिले के महाड के पास हिरकनिवाडी गांव के एक लॉज से पकड़ा गया था। पिछले साल पुणे की मुलशी तहसील के धडवाली गांव में एक भूमि विवाद को लेकर मनोरमा द्वारा कुछ लोगों को कथित तौर पर बंदूक का भय दिखाकर धमकाने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने उनकी और उनके पति दिलीप खेडकर की तलाश शुरू कर दी थी। पुणे देहात की पौड पुलिस ने खेडकर दंपति और पांच अन्य पर आईपीसी की 8

आरा 307 (हत्या का प्रयास), 144 (घातक हथियारों से लैस गैरकानूनी जमावड़ा), 147 (दंगा) और 506 (आपराधिक धमकी) के अलावा शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। इससे पहले, शनिवार को पुलिस ने अदालत को सूचित किया था कि उसने अपराध में इस्तेमाल एक पिस्तौल और एक कार बरामद कर ली है। दरअसल, मनोरमा खेडकर की गिरफ्तारी हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के कारण हुई। जिसमें वह पुणे जिले के मुलशी गांव में जमीन विवाद को लेकर स्थानीय किसानों से झगड़ा करते हुए पिस्तौल लहराते हुए दिखाई दे रही हैं। पुणे पुलिस ने खेडकर दंपति के खिलाफ अवैध हथियार रखने के मामले में आर्मस एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था।

सम्पादकीय

नव तस्करी के खिलाफ लड़ाई

नव तस्करी के खिलाफ हमारी लड़ाई में, हमें लगातार नवाचार के माध्यम से जुड़ने और एकजुट होने का प्रयास करना चाहिए, जिसमें डिजिटल प्रौद्योगिकी के हमारे उपयोग का अनुकूलन भी शामिल है। तस्कर दूसरों का शोषण करने के लिए इंटरनेट की लगातार बदलती प्रकृति का लाभ उठाते हैं यह जरूरी है कि हम भी इस प्रवृत्ति का मुकाबला करने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाएं। डिजिटल तकनीक ने हमें तस्करी को रोकने, पीड़ितों की रक्षा करने, बुरे लोगों पर मुकदमा चलाने और इस अपराध से निपटने के लिए वैश्विक साझेदारी बनाने के नए तरीके दिए हैं। डिजिटल तकनीक और मानव तस्करी के बीच एक तरह का संबंध तब हो सकता है जब तस्कर पीड़ितों का शोषण करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यह कोई नई घटना नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर नए सिरे से ध्यान दिया गया क्योंकि कई लोगों ने कोविड-19 महामारी के चरम पर अपनी दैनिक गतिविधियों को ऑनलाइन कर दिया। कई देशों की रिपोर्टों ने ऑनलाइन वाणिज्यिक यौन शोषण और यौन तस्करी में भारी वृद्धि को प्रदर्शित किया, जिसमें बच्चों का ऑनलाइन यौन शोषण, और बाल यौन शोषण सामग्री की मांग और वितरण शामिल है। तस्करों ने पीड़ितों को तैयार करने, धोखा देने, नियंत्रित करने और उनका शोषण करने के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके व्यक्तियों का शोषण करने की योजनाओं को आगे बढ़ाना जारी रखा है। इनमें से कुछ योजनाएं लोगों को सैकड़ों मील दूर, सीमाओं के पार भी लुभाती हैं, जबकि अन्य के लिए उन्हें अपने घरों से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं होती है। मानव तस्करी के पीड़ितों और बच्चे लोगों ने तेजी से साझा किया है कि वे पहली बार अपने तस्करों से ऑनलाइन जुड़े थे, जबकि तस्कर डिजिटल तकनीकों के अपने उपयोग को परिष्कृत और उन्नत करना जारी रखते हैं, सरकारों और अन्य तस्करी विरोधी हितधारकों को मानव तस्करी से निपटने के लिए ऐसा ही करना चाहिए। तस्कर संभावित पीड़ितों की पहचान और उन्हें तैयार करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं। यूएनओडीसी के अनुसार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तस्करों को सक्रिय रूप से और गुमनाम रूप से एक विशिष्ट प्रकार के व्यक्ति की खोज करने में मदद करते हैं, जिनके बारे में उन्हें लगता है कि वे उनकी योजना को आगे बढ़ाने के लिए विशेष रूप से अतिसंवेदनशील हैं (शिकार प्रक्रिया), या ऑनलाइन पोस्ट करके और प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करके संभावित पीड़ितों को निष्क्रिय रूप से आकर्षित करते हैं (मछली पकड़ने की प्रक्रिया)। अपराधी संभावित पीड़ितों के साथ बातचीत करते समय नकली खातों और प्रोफाइल के माध्यम से अपनी असली पहचान छिपाने के लिए सोशल मीडिया, ऑनलाइन विज्ञापन, वेबसाइट, डेटिंग ऐप और गेमिंग प्लेटफॉर्म—या ऐसे उपकरणों की धोखाधड़ी या भ्रामक नकल—का उपयोग कर सकते हैं। एक बार जब संभावित पीड़ितों की पहचान हो जाती है और संपर्क स्थापित हो जाता है, तो इंटरनेट के माध्यम से संचार शिक्षा, रोजगार, आवास या रोमांटिक संबंधों के झूठे वादों के साथ व्यक्तियों को धोखा देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है, केवल उन्हें श्रम और यौन तस्करी की स्थितियों में लुभाने के लिए। उदाहरण के लिए, एक तस्कर एक ऑनलाइन व्यावसायिक वेबसाइट बना सकता है, जिस पर वे अक्सर पीड़ित का विश्वास जीतने के लिए यथार्थवादी तस्वीरें शामिल करते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि अवसर प्रामाणिक है और उनके करियर को आगे बढ़ाने या उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इंटरनेट शोषणकारी योजना को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में भी काम कर सकता है, जिसमें सेक्सटॉर्शन के माध्यम से भी शामिल है। संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) सेक्सटॉर्शन को एक गंभीर अपराध के रूप में परिभाषित करता है जो तब होता है जब अपराधी पीड़ित द्वारा यौन प्रकृति की तस्वीरें, यौन एहसान या पैसे न दिए जाने पर निजी और संवेदनशील सामग्री वितरित करने की धमकी देता है। इसके अतिरिक्त, तस्कर जबर्न अपराध को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं, जो एक तेजी से आम तंत्र है जिसमें तस्कर अपने पीड़ितों को ऑनलाइन घोटाले के संचालन से लेकर व्यावसायिक सेक्स तक के कार्यों में शामिल होने या उनका समर्थन करने के लिए मजबूर करते हैं। तस्कर बड़े पैमाने पर ऑनलाइन नौकरी लिस्टिंग के माध्यम से पीड़ितों को भर्ती करते हैं, उन्हें परिसरों में बंद कर देते हैं और गंभीर नुकसान की धमकी देकर उन्हें ऑनलाइन आपराधिक गतिविधि में शामिल होने के लिए मजबूर करते हैं। ऑनलाइन घोटाले के संचालन में अवैध ऑनलाइन जुआ, क्रिप्टोकॉरेंसी निवेश योजनाएं और रोमांस घोटाले शामिल हैं, जिनमें से सभी में तस्करी का शिकार व्यक्तियों के साथ संबंध बनाता है ताकि उन्हें महत्वपूर्ण रकम का धोखा दिया जा सके। संक्षेप में, तस्कर अपने तस्करी कार्यों की पहुंच, पैमाने और गति को बढ़ाने के लिए इंटरनेट जैसे डिजिटल उपकरणों का उपयोग करते हैं। हालांकि तकनीकी विकास के साथ तरीके और साधन विकसित हो सकते हैं, लेकिन तस्करी के मूल में शोषण अभी भी जारी है, जो इस अपराध की जांच और उससे निपटने के लिए व्यापक और अभिनव दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। हम सभी को विशेषकर बच्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है या मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। तस्कर आए दिन अपने तरीके बदलते रहते हैं। अपने देश में इस मुद्दे को यानी मानव तस्करी को गृह मंत्रालय मॉनिटर करता है और इस संगठित अपराध को कम करने के लिए संकल्पित भी है। गृह मंत्रालय ने एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग थाने का गठन करने के लिए सभी प्रदेशों को आदेश भी दिया है। आदेश के बाद लगभग राज्यों में इसका गठन हो भी चुका है। साथ ही प्रमुख स्टेकहोल्डर्स के प्रशिक्षण के लिए भी गृह मंत्रालय कार्य कर रहा है।

सत्ता हो विपक्ष, राजनीति तो स्वाभाविक है



mesk prpnhA

जहां तक बजट में राजनीति का सवाल है तो शायद ही कोई सरकार या दल होगा, जिसने अपने कार्यकाल में प्रस्तुत बजट में राजनीति ना की होगी। हर राजनीतिक दल की अपनी विचारधारा है, उसका अपना एजेंडा होता है, उसका अपना वोट बैंक होता है। विपक्षी कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार ने बजट को लेकर राजनीति की है। विपक्ष का आरोप है कि इस बजट में नीतीश कुमार और एन चंद्रबाबू नायडू ने अल्पमत सरकार को समर्थन देने की कीमत वसूली है। आरोप यह भी है कि सरकार बचाने के लिए बीजेपी ने बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज दिया है, जबकि अन्य राज्यों को कुछ खास हासिल नहीं हुआ है। आरोप को बढ़ाते हुए विपक्ष यहां तक कह रहा है कि यह पूरे देश का बजट नहीं है। कांग्रेस तो यहां तक कह रही है कि मौजूदा बजट उसके चुनाव घोषणा पत्र की कॉपी है। जहां तक बजट में राजनीति का सवाल है तो शायद ही कोई सरकार या दल होगा, जिसने अपने कार्यकाल में प्रस्तुत बजट में राजनीति ना की होगी। हर राजनीतिक दल की अपनी विचारधारा है, उसका अपना एजेंडा होता है, उसका अपना वोट बैंक होता है। बजट हो या अन्य सरकारी फैसले, हर राजनीतिक दल और सरकार अपने कदम उठाते वक्त उनका ध्यान रखती है। इसके साथ ही हर राजनीतिक दल अपने भावी और लक्षित वोट बैंक को लुभाने के लिहाज से भी फैसले लेता है। हर राजनीतिक दल की चाहत होती है कि उसका मौजूदा वोट आधार बढ़े। इस लिहाज से भी वह अपने राजनीतिक फैसले लेता है और उसकी सरकारें भी अपनी नीतियां इसी हिसाब से बनाती और बढ़ाती हैं। इस नजरिए से देखें तो अगर मोदी सरकार ने नीतीश और नायडू के राज्यों को कुछ विशेष सहूलियतें दी हैं तो कोई गलत नहीं है। अगर बिहार बाकी राज्यों की तुलना में पिछड़ा है, वह जनसंख्या पलायन का दंश झेलने को मजबूर है तो हर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस देश के साथ कदमतल करने के लिए बिहार को अगर सहूलियत देनी पड़ी तो दे। मदद का हाथ बढ़ाना पड़े तो बढ़ाए। अगर आंध्र प्रदेश को भी मदद की दरकार हो तो मिलनी चाहिए। सिर्फ बिहार और आंध्र ही नहीं, जो राज्य पिछड़ा है, उसे आगे लाने और उसे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मदद की स्पष्ट नीति होनी चाहिए। अब तो हम देश को एक इकाई के तौर पर देखने का दावा करते

हैं। अपना संविधान नागरिक को देश की मूल इकाई घोषित करता है। इस लिहाज से हर नागरिक बराबर है। लेकिन आर्थिक और सामाजिक नजरिए से देखें तो हर नागरिक बराबरी की बेंच पर नहीं बैठा है। समान मतदान और कानून के सामने बराबरी के अधिकार ने एक हद तक बराबरी की इस अवधारणा को जिंदा जरूर रखा है। यह बात और है कि अक्सर अमीर और गरीब के लिए कानूनी पेच और प्रक्रियाएं, यहां तक कि न्यायिक अवधारणा भी बदल जाती है। इन बातों को छोड़ दें तो कम से कम आर्थिक आधार पर बराबरी की ओर बढ़ने की कोशिश होनी चाहिए। प्रशासनिक सहूलियत और सांस्कृतिक आधार पर हमने राज्य गठित कर लिए तो इसका यह मतलब नहीं कि उनकी असमानताओं को अनदेखी की जाए। किसे नहीं पता है कि बिहार के उत्तरी हिस्से में हर साल कोसी नदी प्रलय लेकर आती है। जिससे तकरीबन आधा बिहार नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर रहता है। इसी तरह समूचे देश को पता है कि तेलंगाना के अलग होने के बाद हैदराबाद आंध्र की राजधानी नहीं रहा। उसे राजधानी बनाने के लिए संसाधन चाहिए ही होंगे। इसलिए अगर बिहार और आंध्र को सहूलियतें कुछ ज्यादा मिली भी हैं तो उसे राजनीतिक चश्मे से देखने की बजाय जमीनी हकीकत के लिहाज से समझा जाना चाहिए। वैसे यह भी अर्थात् सत्य ही है कि बाकी राज्यों को बजट में कुछ नहीं मिला। जबकि इस बजट में अगर रेल परियोजनाएं हैं, अगर कृषि बजट को सवा लाख करोड़ से बढ़ाकर एक करोड़ 52 लाख करोड़ कर दिया गया है, अगर सड़क परियोजनाओं की बाढ़ लाई गई है, अगर केंद्रीय करो में राज्यों का हिस्सा बढ़ाया गया है तो इससे किसी एक ही राज्य का भला नहीं होना है, बल्कि देश के हर राज्य को भला होना है। बजट में आदिवासी लोगों के लिए बजट में वित्त मंत्री पूर्वोदय योजना लेकर आई हैं। जिसके जरिए झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। झारखंड को एक और योजना का सीधा फायदा मिलेगा। बजट प्रस्तावों में 'प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान' योजना भी लायी गई है। आदिवासी गांवों और लोगों के विशेष विकास के लिए विशेष रूप से डिजाइन इस योजना का फायदा उन सभी राज्यों को मिलना है, जहां आदिवासी आबादी है। झारखंड में जहां 27 फीसद आबादी जनजातीय है। वहीं उसके पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में करीब 32 फीसद आबादी जनजातीय समुदाय की है। 'प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत

ग्राम अभियान' के दायरे में 63 हजार गांवों को लाया जाना है। जिससे सीधे तौर पर पांच करोड़ जनजातीय लोगों की जिंदगी बदलने की कोशिश की जानी है। जाहिर है कि इसका फायदा उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ कांग्रेस शासित तेलंगाना को भी मिलेगा, क्योंकि इन्हीं राज्यों में देश का सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी रहती है। कांग्रेस ने युवाओं को लुभाने के लिए तीस लाख खाली पड़े सरकारी पदों को भरने और डिप्लोमा धारक सभी बेरोजगार युवाओं को इंटरनशिप और एक लाख रूपए सालाना देने का वादा किया था। राहुल गांधी और उनके सहयोगियों ने इस वायदे को खूब प्रचारित किया। राहुल गांधी कहा करते थे कि इस सरकार बनी और उधर खटाखट-खटाखट खाते में पैसे ट्रांसफर होने लगे थे। माना जाता है कि इससे युवाओं का एक वर्ग विपक्ष की ओर आकर्षित भी हुआ। कांग्रेस की सीटें बढ़ने में इस वायदे की भी बड़ी भूमिका मानी जा रही है। बजट में सरकार ऐसी योजना तो लेकर नहीं आई, अलबत्ता वह युवाओं के लिए इंटरनशिप योजना लेकर आई है। जिसके तहत हर साल एक करोड़ युवाओं को इंटरनशिप दी जानी है, जिसके लिए उन्हें पांच हजार रूपए मासिक और एक मुश्त साल में एक बार छह हजार रूपए भी दिए जाने हैं। करीब चार करोड़ दस लाख युवाओं को कुशल बनाने की भी योजना लाई गई है। इन्हीं योजनाओं का हवाला देकर कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है कि उसके वायदे को सरकार ने कॉपी कर लिया है। इसके बहाने वह कांग्रेस पर हमलावर भी है। चाहे सरकार को विपक्ष, सबका दावा है कि उनकी राजनीति का उद्देश्य देश के लोगों का जीवन स्तर सुधारना है। सवाल यह है कि जब सबका यही उद्देश्य है तो कल्याणकारी योजनाएं कोई भी लाए, उसे खुश होना चाहिए। कांग्रेस को तो वाकई में प्रसन्न होना चाहिए कि उसका वायदा इतना ताकतवर रहा कि उसे अपनाते के लिए उसकी कट्टर विरोधी बीजेपी की सरकार को मजबूर होना पड़ा। लेकिन हकीकत में कांग्रेस खुश नहीं है, उसे लगता है कि सरकार ने सत्ता के जरिए उसका मुद्दा लपक लिया है। कांग्रेस को डर है कि अगर इस प्रस्ताव को ईमानदारी से लागू कर दिया गया तो उसकी ओर आकर्षित हो रहे युवाओं के आकर्षण में कमी आ सकती है। जिसकी वजह से उसे सियासी नुकसान हो सकता है या भविष्य में जितने फायदे मिलने की उम्मीदें रहीं हैं, वह पूरा नहीं हो पाएगा। सत्ता संभालने की बात हो या उसके विरोध की, सबका उद्देश्य जब राजनीति ही है तो फिर सरकारी कदमों में राजनीति ना होने की उम्मीद पालना बेमानी ही कहा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी अगर राजनीति में हैं तो वह संत की भूमिका निभाने के लिए नहीं हैं और अगर राहुल भी राजनीति में हैं तो वह अध्यात्म की सेवा करने के लिए नहीं हैं। इसलिए बजट हो विरोध, राजनीति होगी। लिहाजा बजट को लेकर आरोप लगाना कि यह राजनीति बजट है, उसका कोई मतलब नहीं। राजनीति तो यह समझती ही है, आम वोटों को भी यह जल्द से जल्द समझ लेना चाहिए।

अखिलेश बोले: अयोध्या मामले में हो डीएनए टेस्ट, अवधेश प्रसाद ने कहा- रोज सैकड़ों लोग हमारे साथ फोटो हैं खिंचाते



लखनऊ (संवाददाता)। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भद्ररसा मामले में बिना डीएनए टेस्ट के भाजपा का आरोप दुराग्रहपूर्ण माना जाएगा। फैजाबाद के सांसद ने भी अपने सांसद आरोप की तस्वीर पर चुप्पी तोड़ी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या के भद्ररसा मामले में बिना डीएनए टेस्ट के भाजपा का आरोप दुराग्रहपूर्ण माना जाएगा। कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है, उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसफ का रास्ता निकाला

जाए न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हों, उन्हें कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए। अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हों, तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी न बख्शा जाए। अखिलेश यादव ने जारी बयान में मांग की है कि सरकार पीड़ित परिवार को तत्काल 20 लाख रुपये की सहायता दे। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। हर दिन हत्या, लूट, दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं। भाजपा सरकार असली अपराधि

यों को बचाती रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा अयोध्या की हार पचा नहीं पा रही है। भाजपा ने अयोध्या में पिछले सात वर्षों में जो भ्रष्टाचार और जमीनों की लूट की है। लोकसभा चुनाव हारने के बाद भाजपा बौखलाई हुई है। बिना जांच पड़ताल के समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की नीयत से आरोप लगाना राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित है। अखिलेश ने कहा कि लखनऊ की घटना में भी समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की नापाक और असफल कोशिश की गई थी, जबकि सपा ने उस घटना की पहले ही निंदा की थी। उसमें तीन दर्जन नामों की चर्चा है। भाजपा में हिम्मत है तो वह तथाकथित आरोपियों के बारे में श्वेतपत्र जारी करे। भाजपा साजिश के तहत समाजवादी पार्टी के खिलाफ झूठे आरोप लगाती रही है। सांसद अवधेश प्रसाद ने शनिवार को भद्ररसा दुष्कर्म मामले में बयान दिया है। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में उन्होंने कहा कि यह घटना बहुत की दर्दनाक व शर्मनाक है।

इसकी जितनी निंदा की जाए, कम है। इस घटना से संबंधित जो भी लोग हैं, उनकी विवेचना की जाए। सत्य का पता लगाया जाए और जो भी दोषी हों, कानून के हवाले कर उनके खिलाफ जो भी सजा देता है, सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कहा कि पुलिस अधिकारी व विवेचक को चाहिए कि किसी के दबाव में न आकर दूध का दूध पानी का पानी अलग करें। पीड़िता के साथ उसे न्याय दिलाने के लिए हमारी पार्टी और हम पूरी तरह खड़े हैं। भाजपा इस पर राजनीति कर रही है। जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। निर्दोष को फंसाया न जाए। इसकी और हकीकत के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाए। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। मैंने अपनी 45 साल की राजनीति में कभी ऐसे लोगों का साथ नहीं लिया। जहां तक तस्वीर का सवाल है, हम लोग राजनीति करते हैं। चुनाव से लेकर जीतने तक लाखों लोगों ने फोटो खिंचाई, सेल्फी ली। रोज 500 लोग फोटो खिंचाते हैं।

राजकीय पौधशालाओं पर पौधों की दरें, साइन बोर्ड पर अंकित करें- उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह

लखनऊ (संवाददाता)। प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने सभी जिला उद्यान अधिकारी, अधीक्षक राजकीय उद्यान और आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीन संचालित राजकीय पौध शालाओं पर पौधों की दरें, साइन बोर्ड पर अंकित कराएं। उन्होंने कहा कि जिन जनपदों की राजकीय पौधशालाओं पर पौधों की दरें, साइन बोर्ड पर अंकित नहीं मिलेंगी, उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। प्रदेश में कुल 139 राजकीय पौधशालायें संचालित हैं, जहां पौध उत्पादन का कार्य होता है। उद्यान मंत्री ने कहा कि राजकीय पौध शालाओं पर कलमी फलदार तथा बीजू पौधों की दरें साइन बोर्ड पर अंकित होने से किसानों और आम जनता को पौधों की सही दरें ज्ञात हो सकेंगी जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। पौधों की दरें साइन बोर्ड पर अंकित होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और जनता को पौधों की दरों की सही जानकारी मिलेगी।

कांवड़ यात्रा मार्गों, शिवालयों व धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं को न हो असुविधा

लखनऊ (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा ने कहा कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और आगे राष्ट्रीय पर्व, धार्मिक त्यौहार आने वाले हैं, इस दृष्टि से सभी निकाय अपने क्षेत्रों की बेहतर साफ सफाई, स्वच्छता, मार्ग प्रकाश, जलापूर्ति, जल निकासी तथा स्वच्छता सर्वेक्षण आदि कार्यों पर विशेष ध्यान देंगे। सभी निकाय अपने क्षेत्रों में अमृत सरोवरों, पार्कों, वैंडिंग जोन आदि में 09 से 15 अगस्त, 2024 तक राष्ट्रीय पर्व, हर घर तिरंगा कार्यक्रम, शहीदों को नमन, काकोरी दिवस को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराए और नागरिकों को स्वच्छता के प्रति तथा प्लास्टिक मुक्त निकाय के लिए जागरूक करें। उन्होंने निकायों के बेहतर व्यवस्थापन के लिए सभी अधिशासी अधिकारियों को अपने निकाय के मुख्यालय क्षेत्र में ही रहने के निर्देश दिए और कहां की अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन करने के पश्चात ही उनकी अच्छे निकायों में नियुक्ति की जाए या अतिरिक्त प्रभार दिया जाए। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा रविवार को डी ट्रिपल सी लाइव मॉनिटरिंग के माध्यम से सभी निकायों के कार्यों की वर्चुअल समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बलिया, बुलंदशहर, शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, हाथरस, चित्रकूट, गोलाबाजार, गोलागोकर्णनाथ, बहराइच, बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव, बस्ती, देवरिया, बलिया, इटावा, शामली, कन्नौज, सीतापुर, मिर्जापुर, बड़हलगांज, चंदौली, वाराणसी, अयोध्या, कानपुर नगर, लखनऊ आदि निकायों के अधिकारियों से वर्चुअल संवाद कर स्थितियों का जायजा लिया तथा निकायों के व्यवस्थापन के अहम निर्देश दिए। ए.के. शर्मा ने निर्देशित किया कि कावड़ यात्रा मार्गों, धार्मिक स्थलों, शिवालयों एवं प्रमुख मंदिरों के आसपास साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था करने के साथ इन क्षेत्रों की सड़कें और गलियां साफ सुथरी और गड्ढा मुक्त हो, मार्गों में प्रकाश की व्यवस्था हो, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करें। सामुदायिक, सार्वजनिक व पिक शौचालयों की साफ सफाई तथा मोबाइल टॉयलेट आदि की व्यवस्था हो, कूड़ा इधर उधर न फैले इसके लिए डस्टबिन रखवाएं। कूड़े का नियमित उठान कराए और एमआरएफ सेंटर ले जाकर सोर्स सेग्रीगेशन कर कूड़ा प्रबंधन पर ध्यान देंगे। पूजा स्थलों से निकलने वाली सामग्री का बेहतर निपटान कराए या इससे अगरबत्ती, धूप दीप, हवन सामग्री आदि बनवाने का भी प्रयास करें। नगर विकास मंत्री ने कहा कि बरसात का मौसम है सभी निकाय जल निकासी के बेहतर प्रबंध करें, पंपिंग स्टेशन, जेट पंप और पंपिंग सेट चालू हालत में हों, वॉटर लॉगिंग न हो नालेधनालियों की सफाई पर ध्यान देंगे। बरसात में संचारी रोगों की रोकथाम तथा मच्छर और मक्खी जनित बीमारियों, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकने के लिए एंटीलार्वा दवा का छिड़काव करें। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की साफ सफाई कराने तथा रोगों की रोकथाम का भी प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी निकाय स्वच्छता को लेकर नागरिकों को जागरूक करें, स्वच्छता स्लोगन लिखवाए, प्लास्टिक मुक्ति अभियान चलाएं, लोगों को प्लास्टिक प्रयोग न करने के लिए भी जागरूक करें। सीवर व गटर का पानी रिहायसी इलाकों में न भरे, सीवर का पानी जलापूर्ति में न मिले, सीवर सफाई पर भी ध्यान देंगे। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने कहा कि नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने में सभी निकाय पूर्ण मनोयोग से कार्य करें, इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यों को बेहतर ढंग से करने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा ले, कार्यों की ज़ोन से मॉनिटरिंग कराए। त्योहारों में दुर्घटना मुक्त कार्यक्रम हो, ऐसी व्यवस्था करें। निकायों को ओडीएफ प्लस प्लस बनाना है। निकायों में कुल 771 वेस्ट टू वैंडर पार्क बनाए गए हैं, इन पार्कों में राष्ट्रीय पर्व के दौरान स्थानीय लोगों की भागीदारी से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराया जाए।

यूपी: कांग्रेस ने उपचुनाव को लेकर कसी कमर, सभी दस जिलों में तैनात होंगे प्रभारी, गठबंधन पर रुख किया साफ

लखनऊ (संवाददाता)। प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी तैयारी तेज कर दी है। फिलहाल पार्टी सपा के साथ गठबंधन में उपचुनाव लड़ेगी। इससे पहले तैयारियों को गति देने के लिए सभी दस जिलों में प्रभारी तैनात किए जाएंगे। दूसरी तरफ लोगों को पार्टी से जोड़ने और उनको जागृत करने के लिए प्रदेश भर में प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारी अलग-अलग रात्रि प्रवास करेंगे। अगले दिन सुबह प्रभात फेरी भी निकालेंगे। यह निर्णय शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक में हुआ। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह



आप सभी की कड़ी मेहनत का नतीजा है। लेकिन, हमें रुकना नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा और मेहनत करके प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को जिताना है। उन्होंने कहा कि यह उपचुनाव हमारे लिए प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव का आधार बनेगा। इसलिए हम सभी को पूरी मेहनत के साथ अभी से तैयारियों में

यूपी: अब इस एप के जरिए देख सकेंगे रोडवेज बसों की लाइव लोकेशन, ड्राइवरों की ड्यूटी लगाने में भी होगा इस्तेमाल

लखनऊ (संवाददाता)। रेलवे की तर्ज पर अब आप यूपी रोडवेज की बसों की लाइव लोकेशन देख सकेंगे। 15 अगस्त से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इसकी शुरुआत कर सकते हैं। यूपी की रोडवेज बसों में सफर करने वाले यात्रियों को आने वाले समय में सुगमता की जा रही है। ड्राइवरों की ड्यूटी लगाने, टिकटिंग व बसों की लाइव लोकेशन जानने के लिए तीन एप की जगह अब सिर्फ एक एप सुगम का इस्तेमाल होगा। इससे यात्रियों और कर्मियों को खासी राहत मिलेगी। इस एप का शुभारंभ 15 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। रेलवे की तर्ज पर सुगम एप से ही बसों की लोकेशन व टाइमटेबल आदि की जानकारी मिल सकेगी। इस एप को ऑल इन वन बनाने के लिए रोडवेज प्रशासन ने दूसरे एप व सिस्टम को एकीकृत करने की योजना बनाई है। रास्ते में बस खराब होने पर ड्राइवर इस एप पर शिकायत भी दर्ज करवा सकेंगे। एप बनने से संविदा कर्मियों की ड्यूटी भी ऑनलाइन लग सकेगी। इससे ड्यूटी लगाने में भेदभाव की शिकायतें भी रुकेंगी। साथ ही ड्यूटी लगाने में होने वाली कमीशनबाजी भी रुकेगी। यूपी रोडवेज में हैं 11,500 बसें और 32 हजार संविदाकर्मी— रोडवेज के बेड़े में 11,500 बसें और 32 हजार संविदाकर्मी हैं— 16 लाख से अधिक यात्री रोजाना बसों से करते हैं सफर— प्लेट में नई बसें जुड़ने के बाद 18 लाख रोजाना हो जाएंगे यात्री— 120 इलेक्ट्रिक व एक हजार डीजल बसें महाकुंभ से पहले जुड़ेंगी आसानी से होगी ट्रेकिंग वर्तमान में तीन एप चल रहे हैं। इन सभी को एकीकृत कर सुगम एप बनाया गया है। लोकेशन ट्रेकिंग, टिकटिंग, ड्यूटी अलॉटमेंट के सारे कार्य अब सुगम एप से होंगे।

लगाना है। अजय राय ने संगठन को और अधिक मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने प्रभारी सचिवों को उनके प्रभार क्षेत्र में अनिवार्य रूप से जाकर काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला, शहर कमेटीयों के भौतिक सत्यापन के लिए जिला कमेटी की बैठकों में प्रभारी महासचिवों, सचिवों को अवश्य उपस्थित रहने को कहा। साथ ही जिलों में फ्रंटल संगठनों, विभागों, प्रकोष्ठों के चेयरमैनो के साथ बैठक कर फ्रंटल संगठनों, विभागों व प्रकोष्ठों की जिला, शहर कमेटी की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। बैठक में पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, शिव पांडेय, प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश सिंह, विश्वविजय सिंह, मकसूद खान, शरद मिश्रा, विवेकानंद पाठक आदि उपस्थित थे। हर पदाधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी प्रदेश अध्यक्ष ने जिलों और शहरों में हर पदाधिकारी की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की। इसके अन्तर्गत न्यूनतम पांच उपाध्यक्ष नियुक्त करते हुए उनके कार्य निर्धारित किए तथा हर विधानसभा पर महासचिव प्रभारी, प्रत्येक ब्लॉक पर सचिव प्रभारी बनाने को कहा। इसी तरह शहरी क्षेत्र में बड़े पांच वार्डों पर महासचिव, हर बड़े दो वार्ड पर सचिव बनाने साथ ही हर माह जिला, शहर कांग्रेस कमेटीयों को समीक्षा रिपोर्ट देने को कहा। इस अवसर पर अजय राय ने नवनिर्वाचित सांसद तनुज पुनिया तथा राकेश राठौर का स्वागत किया।

फाइलेरिया से बचाव की दवा खाएं, सभी को इस बीमारी से बचाएं : सीएमओ

(संवाददाता)

फतेहपुर। मच्छरों के काटने से होने वाली फाइलेरिया यानि हाथीपांव एक लाइलाज बीमारी है। मच्छर हम सभी को काटते हैं, इसलिए यह बीमारी किसी को भी हो सकती है। बीमारी की गंभीर स्थिति में रोगी के प्रभावित अंगों (हाथ-पैर, अंडकोश, स्तन) में इतनी सूजन आ जाती है कि वह अपनी दैनिक दिनचर्या भी नहीं कर पाता। यह बीमारी न हो इसके लिए 10 अगस्त से सामूहिक दवा सेवन ट्रिपल ड्रग थैरेपी आईडीए अभियान चलाकर घर-घर लोगों को फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाई जाएगी। उक्त बातें मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ राजीव नयन गिरी ने कहीं। वह मंगलवार को जनपद के एक स्थानीय होटल में फाइलेरिया आईडीए अभियान के संबंध में सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च (सीफार) के सहयोग से आयोजित एक दिवसीय मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी मीडिया बंधुओं से अपेक्षा किया कि विभिन्न संचार माध्यमों के जरिये फाइलेरिया मुक्त भारत का संदेश जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करें। सीएमओ ने कहा कि 10 अगस्त से दो सितम्बर तक ट्रिपल ड्रग थैरेपी आईडीए (आइवर्मेक्टिन डीडीसी

एल्बेण्डाजोल) अभियान जनपद के सभी ब्लॉक सहित षहरी क्षेत्र में चलने जा रहा है। इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को अपने सामने फाइलेरिया रोधी दवा खिलाएंगे। उन्होंने बताया कि इस अभियान में 'आइवर्मेक्टिन डीडीसी एल्बेण्डाजोल' तीन दवाओं की आयु के अनुसार निर्धारित खुराक खिलाई जाएगी। यह दवा दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और अति गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को नहीं खिलाना है। पेश सभी लोगों को यह दवा खिलाई जाएगी। दवा खाली पेट नहीं खानी है और दवा की सही खुराक सभी सेवन कर लें इसलिए इसे स्वास्थ्यकर्मी के सामने ही खाना आवश्यक है। जिला मलेरिया अधिकारी कीर्ति रंजन ने जनसमुदाय से अपील किया कि जब भी आषा कार्यकर्ता व उनकी सहयोगी दवा खिलाने जाएं तो उनका सहयोग करें। घर के सभी पात्र लाभार्थी को दवा अवष्य खिलाएं। दवा खिलाने के लिए बनाई गई प्रत्येक टीम एक दिन में 25 घर जाकर दवा खिलाएगी। उन्होंने बताया कि जनपद की 29 लाख 20 हजार लक्षित आबादी को आच्छादित करने के लिए 2525 टीम बनाई गई हैं। दवा का सेवन कराने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मियों को

प्रशिक्षित किया गया है। इसके पर्यवेक्षण के लिए कुल 421 सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं। इस अवसर पर राधेप्याम भारती वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक,ईषान महंत और आषीश त्रिपाठी,मलेरिया निरीक्षक और सहयोगी संस्था पाथ से डा रवि राज सिंह ,पीसीआई से जिला समन्वयक स्मृति श्रीवास्तव और सीफार के जिला समन्वयक सुबोध दीक्षित ,रोहित माली ब्लॉक समन्वयक उपस्थित रहे।

सुरक्षित व कारगर हैं दवाएं सहयोगी संस्था पाथ के क्षेत्रीय एनटीडी अधिकारी डॉ रविराज चौहान ने बताया फाइलेरिया से बचाव की दवाएं डबल्यूएचओ द्वारा प्रमाणित हैं। यह दवाएं सुरक्षित हैं व फाइलेरिया रोग से बचाव में कारगर हैं। कुछ लोगों को फाइलेरिया से बचाव की दवा खाने के कुछ देर बाद सिरदर्द, बुखार, उल्टी, बदन में चकत्ते और खुजली जैसी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं। इससे घबराना नहीं है। यह षरीर में मौजूद फाइलेरिया के सूक्ष्म परजीवी के नश्ट होने की वजह से होता है और आमतौर पर यह स्वतः ठीक हो जाता है। अगर किसी को ज्यादा दिक्कत हो तो आषा कार्यकर्ता के माध्यम से ब्लॉक रिस्पांस टीम को सूचित कर सकता है।

हर घर तिरंगा अभियान के तहत फहराए जायेगे 6 लाख 80 हजार झंडे

(संवाददाता)

फतेहपुर। स्वतंत्रता दिवस पर 13 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक हर घर तिरंगा अभियान एवं 09 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन षताब्दी महोत्सव के सफल क्रियान्वयन हेतु तैयारियों के सम्बन्ध में एक बैठक कलेक्ट्रेट महात्मा गांधी सभागार में जिलाधिकारी सी० इन्दुमती की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी विभाग हर घर तिरंगा कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करें तथा सभी विभागों में जहां पर तिरंगा फहराया जाना है, चिन्हित कर नोडल अधिकारी नामित कराये एवं यह भी सुनिश्चित करे कि तिरंगा झण्डा फहराते समय की फोटोग्राफस सुस्पष्ट हो ताकि निर्धारित वेबसाईट पर अपलोड की जा सकें। खण्ड विकास अधिकारी, अधिषाशी अधिकारी, एआरटीओ, पुलिस विभाग एवं अन्य विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन विभागों को जो लक्ष्य मिला है, जिला पंचायत राज अधिकारी को अवगत कराये तथा झण्डा फहराते समय सेल्फी, फोटोग्राफस, रील अवष्य बनायें। जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि जनपद फतेहपुर में 06 लाख, 80 हजार झण्डे लगाये जाने है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिये उपायुक्त स्वतः रोजगार के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा 04 लाख 74 हजार झण्डे का निर्माण काराया जा रहा है एवं षहरी क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय षहरी आजीविका मिषन के स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा 02 लाख 06 हजार तिरंगा झण्डो का निर्माण काराया जा रहा है। उन्होने बताया कि प्रत्येक नागरिक को अपने आवास, स्कूल, सरकारी कार्यालयों में झण्डा सम्मान के साथ झण्डा संहिता

का अनुपालन करते हुए फहराना / लगाना, झण्डा लगाते / फहराते समय सदैव केसरिया रंग की पट्टी झण्डे के ऊपर की तरफ होनी चाहिये। आवासों एवं प्रतिष्ठानों में लगाये जाने वाले झण्डों को उक्त समय अवधि के उपरान्त आदर भाव के साथ उतार कर सुरक्षित रखा जाय। विशेष परिस्थितियों में झण्डा रात्रि में भी फहराया जा सकता है। झण्डे का निर्माण 03 अनुपात 02 में होना चाहिये, झण्डे का आकार आयताकार हो, झण्डे में तीन रंगों में सबसे उपर केसरिया, बीच में सफेद तथा नीचे हरे रंग का प्रयोग कर बनाये, साथ ही सफेद पट्टी में 24 तीलियों वाले अषोक चक को बाद में प्रिन्ट काराया जाना है। जिलाधिकारी ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में काकोरी ट्रेन एक्शन एक महत्वपूर्ण घटना है। इसके 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर काकोरी ट्रेन एक्शन षताब्दी समारोह जनपद में 09 अगस्त को गरिमापूर्ण भाव में मनाया जाय। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, चित्रकला/पेटिंग, सुलेख एवं निबन्ध, भाषण एवं वाद विवाद, प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा। सभी स्कूलों व संस्थाओं में आजादी के नायको के चित्र देष भक्ति नारे, लिखी प्रटीकाओं को हाथ में लेकर प्रभात फेरी निकाली जायेगी। षैक्षणिक संस्थानों के प्राचार्यों/अध्यापकों द्वारा प्रार्थना सभा के समय काकोरी ट्रेन एक्शन/घटनाओं पर विधिवत प्रकाष डालते हुए छात्र/छात्राओं को पढ़कर सुनाया जायेगा। इसके अतिरिक्त समस्त षहरी स्मारकों, स्मृति स्थलों, अमृत सरोवरो, अमृत वाटिकाओं पर उपस्थित सम्मानित नागरिकों को काकोरी ट्रेन एक्शन को वृत्तंत को पढ़कर सुनाया जायेगा। साथ ही काकोरी ट्रेन एक्शन पर आधारित चित्र व अभिलेख प्रदर्षनी का आयोजन किया जायेगा।

स्वच्छता अभियान, पौधरोपण, सेवा समर्पण, राष्ट्र धुन एवं ब्रास बैंड का वादन आदि कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी पवन कुमार मीना, अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व), अपर जिलाधिकारी न्यायिक, समस्त उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, वनाधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, परियोजना निदेशक डीआरडीए, उपायुक्त स्वता: रोजगार, डीसी मन्रेगा, एआरटीओ, समस्त खंड विकास अधिकारी, ईओ सहित संबंधित उपस्थित रहे।

अलग-अलग सड़क हादसों में चार घायल

फतेहपुर। जनपद के अलग-अलग थाना क्षेत्रों के अंतर्गत हुए सड़क हादसों के दौरान महिला समेत चार लोग घायल हो गए। जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जहां महिला समेत दो की हालत गंभीर देख कानपुर के लिए रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार हमीरपुर जनपद के मौदहा निवासी इलियास अपनी 30 वर्षीय पत्नी षीरीन को लेकर षहर के ज्वालागंज मिट्टी में षामिल होने आ रहे थे। जैसे ही बाइक मलवां थाना क्षेत्र के चक्की गांव के पास पहुंची तभी अचानक चलती बाइक से महिला गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। इसी प्रकार थरियांव थाना क्षेत्र के बिलंदा गांव निवासी मो. रमजान का 50 वर्षीय पुत्र मो. कमाल ई-रिक्षे में बैठा था। तभी गांव के समीप ही तेज रपतार आ रहे बाइक से ई-रिक्षा की भिड़ंत हो गई। जिससे वह बुरी

सघर्षशील बच्चों की पहचान कर चलाएं रेमेडियल क्लास

कौषाम्बी। जिला प्रषिक्षण संस्थान में षिक्षक संकुलों की त्रैमासिक बैठक डायट प्राचार्य निधि षुक्ला की अध्यक्षता में ब्लाक

षिक्षक-षिक्षिकाओं एवं बच्चों को बाटे प्रशस्ति पत्र

(संवाददाता)

फतेहपुर। इंडियन रेडक्रास सोसाइटी, आरोग्य भारती व डॉ0 सत्यनारायण सेवा फाउंडेशन के संयुक्त संयोजकत्व में रेडक्रास सोसाइटी के चेयरमैन व आरोग्य भारती के जिला सचिव डॉ0 अनुराग श्रीवास्तव द्वारा विद्यालय के बच्चों व षिक्षिकों के सहयोग से इंडियन रेडक्रास सोसाइटी के वार्षिक सामान्य बैठक में बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गए थे। इस हेतु विद्यालय के षिक्षक व षिक्षिकाओं को प्रशस्ति पत्र व विद्यालय के लिए प्रतीक चिन्ह प्रधानाचार्या सीमा बाजपेयी को दिया गया। इसके पहले बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों के प्रकोप से बचाव हेतु होमियोपैथिक औषधि वितरण अभियान पुनः चलाया गया। डॉ0 अनुराग द्वारा आरजी चिल्ड्रेन अकादमी के 400 बच्चों को बरसात के मौसम में होने वाली संक्रामक बीमारियों से बचाव व रोगप्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में सहायक होमियोपैथिक औषधि का वितरण किया गया। साथ ही डॉ0 अनुराग द्वारा स्वच्छता का विषेश ध्यान रखने हेतु बताया गया जिसमें भोजन से पहले व षौच जाने के बाद साबुन से हाथ धुलने, षुद्ध पानी का इस्तेमाल करने के लिए बताया गया तथा जल संरक्षण हेतु वाटर बेल लगाने, आरओ से वर्थ निकलने वाले पानी को एकत्र कर बर्तन व कपड़े धुलने में इस्तेमाल करने, पर्यावरण संरक्षण हेतु पॉलीथिन के प्रयोग को रोकने हेतु इकोब्रिक्स बनाने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर प्रबंधक संजीव गुप्ता, एडमिनिस्ट्रेषन हेड सुनीता गुप्ता, आदर्ष मिश्रा, आदर्ष दीक्षित, अजय अग्निहोत्री, हिमांषी गौतम, खुषी श्रीवास्तव, दीपिका मौर्या, श्रद्धा वर्मा सहित प्रमुख सहयोगी सुरेष श्रीवास्तव सदस्यता प्रमुख इंडियन रेडक्रास सोसाइटी उपस्थित रहे।

वार संपन्न हुई। सोमवार को प्रथम चरण में मूरतगंज, सरसवां द्वितीय चरण में सिराथू और चायल मंगलवार को प्रथम चरण में मंझनपुर व नेवादा द्वितीय चरण में कौषांबी और कड़ा के षिक्षक संकुलों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

डायट प्राचार्य ने सभी षिक्षक संकुलों को निपुण स्कूल बनाने के लिए फाइव प्वाइंट टूल किट का प्रयोग करने, समय सारिणी व षैक्षिक कैलेंडर के अनुसार पठन पाठन करने, कार्य योजना अपडेट कर क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कक्षा एक से तीन में अद्ययनरत सभी छात्रों का षत प्रतिषत असेसमेंट करने, कार्यपुस्तिका, संदर्षिका, षिक्षण अधिगम सामग्री का अधिकाधिक प्रयोग करने, पंजीकाओ के डिजिटलीकरण करने, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा फार्म अधिक से अधिक भरवाने, पीटीएम बैठक करवाने, स्कूल रेडिनेष कार्यक्रम के संचालन, एजेंडा आधारित षिक्षक संकुल बैठक करने, संघर्षशील बच्चों की पहचान कर रेमेडियल टीचिंग करने, षिक्षकों द्वारा षिक्षण कार्य में किए गए नवाचारों, उत्कृष्ट वीडियो एवं बेस्ट प्रैक्टिसेज षेयर करने के निर्देश दिए। डायट प्रवक्ता धीरज कुमार, एसआरजी ओम प्रकाष सिंह व दिलीप कुमार तिवारी ने षिक्षक संकुलों द्वारा एजेंडा बिंदुओं से संबंधित प्रस्तुतीकरण कर सभी को निपुण षपथ दिलाई।

सुरक्षा प्रक्रिया हेतु आवश्यक बैठक का आयोजन

फतेहपुर। बाल कल्याण समिति एवं चाइल्ड हेल्पलाइन के संयुक्त तत्वाधान में स्टेषन अधीक्षक फतेहपुर, इंस्पेक्टर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इंस्पेक्टर राजकीय रेलवे पुलिस के साथ सवारी गाडी व स्टेषन पर पाए जाने वाले भूले भटके, गुमषुदा बच्चों के पाए जाने पर उनकी देखरेख व सुरक्षा प्रक्रिया हेतु आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में रेलगाडी में व स्टेषन पर भूले भटके, गुमषुदा व तस्करी करके ले जाने वाले बच्चों पर निगरानी तथा आरपीएफ, जीआरपी द्वारा प्राप्त बच्चों को बाल कल्याण समिति में 24 घंटे के अंदर षेष करना तथा षेष करना और उसके बाद बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण से लेकर उनको माता पिता को सुपुर्द करने की जिम्मेदारी बाल कल्याण समिति की हो जाती है। बाल कल्याण समिति उसे अपने विवेका अनुसार माता-पिता को सुपुर्द कर देती है। उनके ना आने पर बच्चों को बाल गृह भेज दिया जाता है।

बतकही हिन्दी साप्ताहिक

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक भूपेंद्र सिंह द्वारा दिशेरा प्रेस, श्याम नगर, खम्भापुर, फतेहपुर से मुद्रित तथा ग्राम- रामपुर पचभिता, मकान नं. 193, पोस्ट- दावतपुर, थाना-मलवां, जिला- फतेहपुर (उ.प्र.) से प्रकाशित।

सम्पादक
भूपेंद्र सिंह